Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

जनवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव 3
- राजस्थान के नए मुख्य सचिव 4
- राजस्थान चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करेगा 4
- राजस्थान चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करेगा 5
- पारंपरिक 'टांकाओं' का आधुनिक अद्यतन 5
- अयोध्या में सीता रसोई के लिये खाना पकाने का तेल 6
- नाबार्ड ने राजस्थान को 1,974 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की 6
- वेटलैंड सिटी प्रमाणन 7

नोट :

राजस्थान

आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है।

- इससे पहले सांभर झील को मार्च 1990 में और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को अक्तूबर 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।

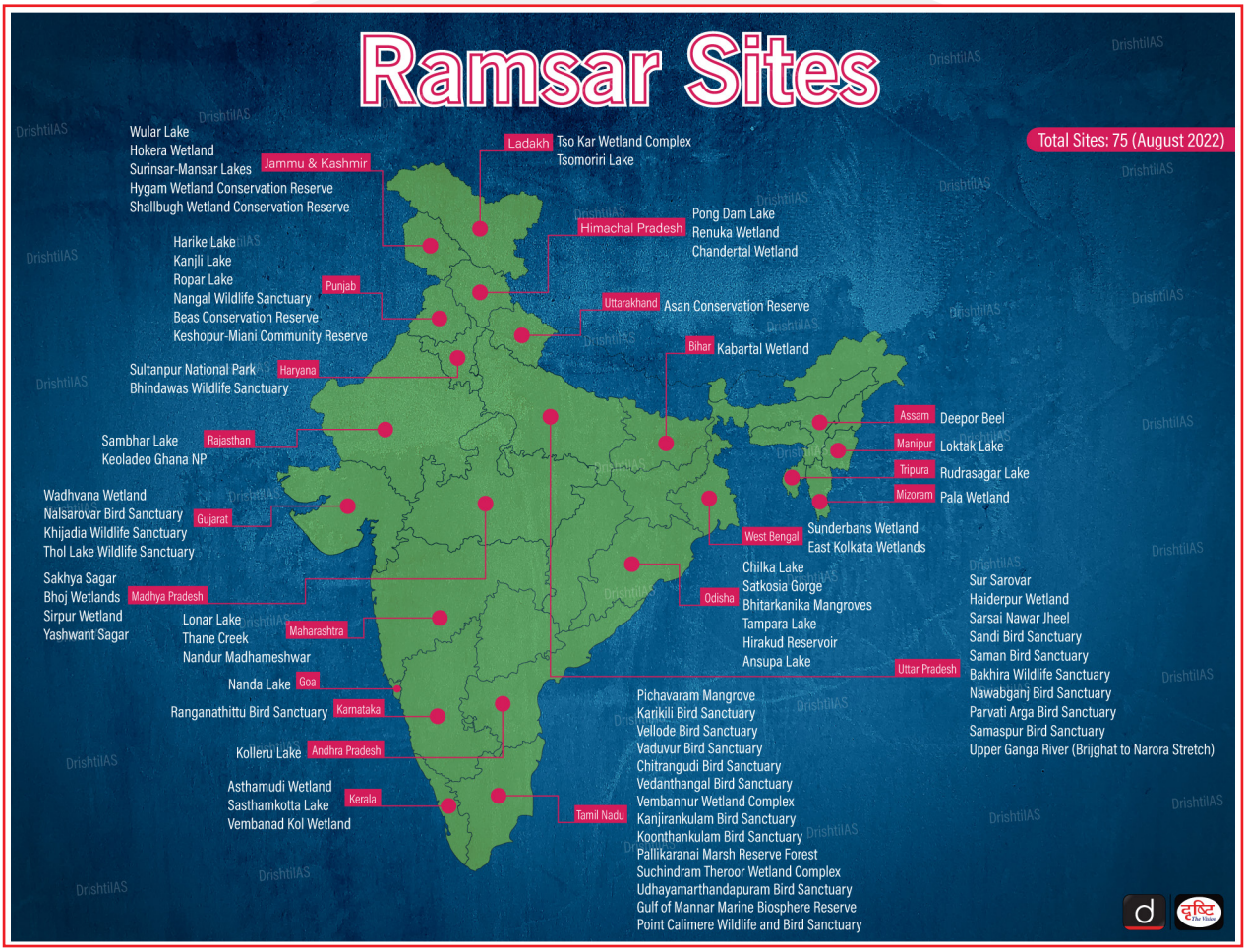

मुख्य बिंदु:

- राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने जोधपुर में खिंचन पक्षी अभयारण्य, जयपुर में चंदलाई, कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लूणकरणसर और उदयपुर ज़िले में मेनार झील का प्रस्ताव दिया है।

नोट :

- अधिकारियों के अनुसार, सभी 5 आर्द्रभूमियाँ मध्य एशियाई फ्लाईवे में आती हैं, जिसका उपयोग प्रवासी पक्षियों द्वारा किया जाता है जो गर्म तापमान के लिये नवंबर से फरवरी तक इस क्षेत्र में उड़ान भरना शुरू कर देते हैं।
- इन स्थलों पर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक अपशिष्टों को पानी में छोड़े जाने से रोकने के लिये कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है।

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन

- यह एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसे 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था।
- भारत में यह 1 फरवरी, 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया।
- 2023 तक, भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं।
- रामसर टैग आर्द्रभूमि के बेहतर रखरखाव और प्रबंधन में मदद करता है और क्षेत्र के लिये पर्यटन को प्रोत्साहित करता है।

राजस्थान के नए मुख्य सचिव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।

- एक साल में सुधांश पंत की यह लगातार तीसरी नियुक्ति है।

मुख्य बिंदु:

- उन्हें अक्तूबर 2022 में जहाज़ मंत्रालय में विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (OSD) के रूप में केंद्र में नियुक्त किया गया, जो बाद में सचिव के पद पर नियुक्त हुए।
- छह महीने के बाद उन्हें सचिव के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
- वरिष्ठ नौकरशाहों के अनिसार निकट भविष्य में सचिव स्तर पर फेर-बदल की उम्मीद है।
- आईएएस अधिकारी डी.एस. मिश्रा का उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल में छह महीने का विस्तार कर दिया गया है।
- वर्ष 1998 बैच की आईएएस अधिकारी वीरा राणा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं।

राजस्थान चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करेगा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एकीकृत करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मांगी है।

मुख्य बिंदु:

- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य योजना के मौजूदा लाभों को बरकरार रखने की उम्मीद है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में ₹25 लाख का बीमा कवर शामिल है।
- राज्य सरकार ने सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों को कवर करने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप ज़िलों को 26 जनवरी, 2024 तक नए कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।
- पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत की ₹5 लाख की तुलना में अधिक कवरेज प्रदान करती है।
- मई 2021 में लॉन्च होने के बाद से, चिरंजीवी योजना के तहत सभी राजस्थानी परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। हाल ही इसका कवरेज ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है, जिसमे दुर्घटना कवरेज के लिये अतिरिक्त ₹10 लाख भी शामिल है।

नोट :

- 100 मिलियन से अधिक परिवारों के पास कम-से-कम एक आयुष्मान कार्ड है जिसमे उत्तर प्रदेश 46 मिलियन के साथ लाभार्थियों की संख्या में अग्रणी है। इसके बाद मध्य प्रदेश (37 मिलियन), गुजरात (20 मिलियन), छत्तीसगढ़ (20 मिलियन), और महाराष्ट्र (19 मिलियन) का स्थान हैं।

राजस्थान चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करेगा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एकीकृत करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंज़ूरी मांगी है।

मुख्य बिंदु:

- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य योजना के मौजूदा लाभों को बरकरार रखने की उम्मीद है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में ₹25 लाख का बीमा कवर शामिल है।
- राज्य सरकार ने सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों को कवर करने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप ज़िलों को 26 जनवरी, 2024 तक नए कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।
- पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत की ₹5 लाख की तुलना में अधिक कवरेज प्रदान करती है।
- मई 2021 में लॉन्च होने के बाद से, चिरंजीवी योजना के तहत सभी राजस्थानी परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। हाल ही में इसका कवरेज ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है, जिसमें दुर्घटना कवरेज के लिये अतिरिक्त ₹10 लाख भी शामिल है।
- 100 मिलियन से अधिक परिवारों के पास कम-से-कम एक आयुष्मान कार्ड है जिसमे उत्तर प्रदेश 46 मिलियन के साथ लाभार्थियों की संख्या में अग्रणी है। इसके बाद मध्य प्रदेश (37 मिलियन), गुजरात (20 मिलियन), छत्तीसगढ़ (20 मिलियन) और महाराष्ट्र (19 मिलियन) का स्थान हैं।

पारंपरिक 'टांकाओं' का आधुनिक अद्यतन

चर्चा में क्यों ?

शुष्क क्षेत्र में जल की कमी से निपटने के लिये, केंद्र ने निकट कंक्रीट के पक्के कुंड का निर्माण करने के लिये पश्चिमी राजस्थान की पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली 'टंका' को अपनाया है।

- टांका एक भूमिगत कुंड है, इसका निर्माण बाड़मेर ज़िला और पश्चिमी राजस्थान के अन्य हिस्सों में लोगों द्वारा जुलाई तथा सितंबर के बीच बारिश के दौरान जल संचयन के लिये किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- पारंपरिक 'टांकों' में संग्रहीत पानी मिट्टी की अपनी संरचना के कारण धीरे-धीरे दूषित हो जाता है और पूरे वर्ष तक नहीं टिक पाता है।
- केंद्र ने लोगों को लंबे समय तक दूषित पानी उपलब्ध कराने के लिये निकट प्रबलित कंक्रीट सीमेंट से बने जल भंडारण स्थानों का निर्माण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम MGNREGA (ग्रामीण) योजना के तहत इस पद्धति को अपनाया है।
- वर्ष 2016 के बाद से कुल 1,84,766 ऐसे टैंकों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 41,580 वर्तमान 2023-24 वित्तीय वर्ष में बनाए गए हैं।
- 13.5 फीट x 13.5 फीट माप वाले प्रत्येक टैंक में 35,000 लीटर जल जमा करने की क्षमता है और इसका निर्माण ₹3 लाख की लागत से किया गया है।
- ज़िले में 2,971 गाँव हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से 'धन्नी' कहा जाता है और संबंधित ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।
- ज़िले के दूरदराज़ के गाँवों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे– जल जीवन मिशन (JJM) योजना के साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा परियोजना से जल की आपूर्ति।
- JJM योजना के तहत 4.25 लाख परिवारों तक पहुँचने का लक्ष्य है। इनमें से 1.25 लाख घर पहले ही कवर किये जा चुके हैं।

नोट :

इंदिरा गांधी नहर

- यह देश की सबसे लंबी नहर है।
- यह पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके बैराज से शुरू होती है, लुधियाना से होकर बहती है तथा उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान में समाप्त होती है।
- यह नहर उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में पीने तथा सिंचाई का एक स्रोत है।
- यह राज्य के आठ ज़िलों के 7,500 गाँवों में रहने वाले 1.75 करोड़ लोगों को जल उपलब्ध करवाती है।
- प्रदूषक तत्त्वों की मौजूदगी के कारण इंदिरा गांधी नहर का जल स्पष्ट रूप से काला हो गया है।
- प्रदूषण के कारण लोगों में त्वचा रोग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अपच और आँखों की रोशनी कम होने जैसी कई स्वास्थ्य जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

अयोध्या में सीता रसोई के लिये खाना पकाने का तेल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अयोध्या में 'सीता रसोई' (Sita's kitchen) के लिये 2,100 खाना पकाने के तेल के ड्रम और 'राम दरबार' शोभायात्रा को रवाना किया।

- तेल का उपयोग 22 जनवरी और उसके बाद राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वाले भक्तों को परोसे जाने वाले भोजन को पकाने के लिये किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- यह कार्यक्रम धर्मयात्रा महासंघ राजस्थान एवं श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति जयपुर की ओर से आयोजित किया गया था।
- जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को अपने घर पर राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिये 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा की।
- शहर में मांस की दुकानें बंद रहेंगी, पाँच लाख तेल के दीपक जलाए जाएंगे और प्रतिष्ठा समारोह के दिन शहर के बाज़ारों में सर्वश्रेष्ठ सजावट के लिये पुरस्कार दिये जाएंगे।

नाबार्ड ने राजस्थान को 1,974 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2023-24 के लिये ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास निधि (RIDF) के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने राजस्थान सरकार को 1,974.07 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु:

- नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार अजमेर, जालोर और कोटा ज़िलों में तीन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिये 930.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- राज्य के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 926.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये।
- इससे पहले राज्य के सभी ज़िलों में 104 पशु चिकित्सालयों और 431 उपकेंद्रों के निर्माण के लिये 117.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये थे।
- पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से 2,500 गाँवों के 2.87 लाख घरों को स्वच्छ और पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जबकि ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से 12 ज़िलों के 1,229 गाँवों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई निधि से 740 करोड़ रुपए की सहायता से 4.28 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने में भी राज्य सरकार का समर्थन कर रहा है।

नोट :

- नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 623.38 करोड़ रुपए की सहायता के बाद कोटा और बूंदी ज़िलों में 450 किलोमीटर लंबी मिट्टी की नहरे निर्माणाधीन है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है।
- इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है।
- यह वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF)

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये की गई थी।
- इस निधि का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा किया जाता है।
- निधि का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चल रही ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

वेटलैंड सिटी प्रमाणन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन (Wetland City Accreditation- WCA) हेतु भारत से तीन शहरों के लिये नामांकन प्रस्तुत किये हैं।

- नामांकित शहरों में इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश) और उदयपुर (राजस्थान) शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- इन शहरों में पाँच प्रमुख आर्द्रभूमियाँ मौजूद हैं जिनमें पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एवं दूध तलाई शामिल हैं।
- ये आर्द्रभूमियाँ शहर की संस्कृति व पहचान का एक अभिन्न अंग हैं जो शहर के माइक्रॉक्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करती हैं और साथ ही मौसम की विषम घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- MoEF&CC की अमृत धरोहर पहल रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देती है जोकि WCA लक्ष्यों के अनुरूप है।

WCA हेतु नामांकित अन्य शहर

- शहर में स्थित एक रामसर स्थल, सिरपुर झील, जिसे जलीय पक्षी समागम के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता दी गई है तथा इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इस शहर में स्थित भोज वेटलैंड (रामसर स्थल) शहर की जीवन रेखा के सामान है जहाँ विश्व स्तरीय वेटलैंड व्याख्या केंद्र स्थापित है जिसका नाम जल तरंग है।

वेटलैंड सिटी प्रमाणन (WCA)

- WCA एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों (Conference of the Contracting Parties- COP) 12, 2015 के सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था, जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा हेतु असाधारण कदम उठाए हैं।
- WCA 6 वर्षों के लिये मान्य होता है।
- इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं परिधीय-शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय आबादी के लिये स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभ अर्जित करना भी है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :